

प्रपक्ष,

मनीषा घंवार

सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,

सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास,

उत्तराखण्ड, देहरादून।

समाज (सैनिक) कल्याण अनुभाग-3 देहरादून दिनांक 12 मई, 2009

विषय: सैनिक कल्याण विभागान्तर्गत कार्यरत ब्लॉक प्रतिनिधियों के मानदेय हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 205/XXVII(1)/2009 दिनांक 25 मार्च, 2009 की छायाप्रति संलग्न कर पेशित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 (01 अप्रैल, 2009 से 31 जुलाई, 2009 तक) के आय-व्यय में सैनिक कल्याण विभाग से संबंधित अनुदान संख्या-15 के आयोजनागत पक्ष में रुपये 7.60 हजार (रुपये सात लाख साठ हजार मात्र) की धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 में वित्त विभाग के उक्त शासनादेश में प्राविधानित एवं निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निरंतर पर रखते हुये व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहित स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या: 205/XXVII(1)/2008 दिनांक 25 मार्च, 2008 में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. अद्यतनबद्ध मदों में व्यय करने से पूर्व सक्षम स्तर का अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।
3. आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित धनराशियों का व्यय निर्धारित परिधाय की सीमा के अंतर्गत ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
4. आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित अन्य धनराशियों हेतु नियमानुसार मांग प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
5. अनुदान के अंतर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग (त्रिमास के आधार पर) अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए, जिससे राज्य स्तर पर कैशफ्लो निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई न उत्पन्न हो।

6. आय-व्ययक द्वारा व्यवस्थित उक्त धनराशि में से केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही व्यय किया जाए और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नए कार्यों के कार्यान्वयन के लिए नहीं किया जाए।
7. उक्त आवंटित धनराशि किसी ऐसी मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका के अंतर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाए।
8. यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाए कि आवश्यकतानुसार आवंटित धनराशि के प्रत्येक बिल में चाहे वह वेतन आदि के संबंध में हो अथवा आकस्मिक व्यय के संबंध में, सम्पूर्ण मुख्य/लघु/उप तथा विस्तृत शीर्षक को अंकित किया जाए और प्रत्येक बिल में दाहिनी और लाल रंगाई से अनुदान संख्या-15 तथा आयोजनागत शब्द स्पष्ट लिखा जाए, अन्यथा महालेखाकार, कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी।
9. संलग्नक में वर्णित धनराशियों का समय से उपयोग करने के लिये यह भी सुनिश्चित कर लें कि धनराशि परिधिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाए। आवंटन एवं व्यय की स्थिति से ध्यासमय शासन को अवगत कराया जाए।
10. मितव्ययिता के संबंध में नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
11. यदि किसी अधिष्ठान/योजनाओं के अंतर्गत अतिरिक्त धनराशि की मांग का औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
12. अप्रयुक्त धनराशि वित्तीय हस्त पुस्तिका के प्राविधानों के अंतर्गत समय-सारिणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
13. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन अपने एवं अधीनस्थ स्तरों पर भी सुनिश्चित करें।
14. समस्त चालू निर्माण कार्य, नए निर्माण कार्य, उपकरण व संयंत्र का क्रय, वाहन का क्रय एवं कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय की स्वीकृतियों के लिए औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को पृथक से उपलब्ध कराएं।
15. बी0एम0-13 पर संकलित मासिक सूचनाएँ नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
16. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-15 के लेखाशीर्षक 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-200-अन्य कार्यक्रम-03-सैनिक कल्याण-0301-सैनिक मुख्यालय के मानक मद 20-सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के नामे डाला जाएगा।

17. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या:-91(P)/XVIII-3/2009, दिनांक 12 मई, 2009 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।  
संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,  
(मनीषा पंचार)  
सचिव।

पृष्ठांक संख्या: 125 (1)/XVIII(1)-3/2009-09/15/2009 तदुद्दिष्ट।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निजी सचिव-मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मण्डलाध्यक्ष, जलवात, उत्तराखण्ड।
5. जिलाधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, कौषाजार एवं वित्त सेक्टर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वरिष्ठ कौषाधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-03, उत्तराखण्ड शासन।
10. वरिष्ठ, राज्यस्तरीय निजीकरण एवं संस्थापन निदेशालय, उत्तराखण्ड स्वीकृतिपरिहार, देहरादून।
11. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, उत्तराखण्ड स्वीकृतिपरिहार, देहरादून।
12. आदेश प्रेषिका।

आज्ञा से,

(सी०एम०एस० बिष्ट)  
अपर सचिव।